

p>

Title: Regarding the constitution of a committee to control the fees hike in schools.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदय, सभी को शिक्षा मिले, यह हमारी सरकार का उद्देश्य है। मैं आपका ध्यान बहुत ही जटिल समस्या की ओर उठाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस तय की जाती है, फीस ही तय नहीं की जाती, बल्कि हर वर्ष बढ़ाई जाती है। यहां तक कि एक बच्चे की फीस एक लाख, डेढ़ लाख रुपये से दो लाख रुपये तक होती है। उसके साथ-साथ किताबें, ड्रेस और स्कूल बस की फीस बाजार रेट से ज्यादा रहती है। जिसके कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना मुश्किल हो गया है।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे राष्ट्रीय नीति बनाएं जिसमें फीस की नीति तय हो। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि राइट टू एजुकेशन आठवीं क्लास तक किया है, अब समस्या आ गई है कि नौवीं क्लास में बच्चे कहां जाएं। उसके लिए भी माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई नीति बनाएं, यही आपके माध्यम से मुझे सरकार से कहना है।